

शिक्षित बेरोजगारों पर सरकारी योजनाओं का प्रभाव बाँका जिला के संदर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन

Divyanshu Kumar Mishra¹ and Dr. Naz Perween²

University Department of Economics

Associate Professor

T. M. Bhagalpur University, Bhagalpur

सारांश

यह अध्ययन बिहार राज्य के बाँका जिले में शिक्षित बेरोजगार युवाओं पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का विश्लेषण करता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी प्रमुख योजनाओं को केंद्र में रखते हुए, यह शोध यह जानने का प्रयास करता है कि क्या ये योजनाएँ बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सार्थक सिद्ध हो रही हैं।¹

प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित इस अध्ययन में 50 शिक्षित बेरोजगार प्रतिभागियों से जानकारी एकत्र की गई। विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि लगभग 60% प्रतिभागियों को इन योजनाओं से कोई सीधा लाभ नहीं मिला। जिन प्रतिभागियों ने योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास किया, उन्हें प्रक्रिया की जटिलता, ऋण अस्वीकृति, प्रशिक्षण की अनुपलब्धता और प्रशासनिक सहयोग के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, यह भी सामने आया कि अधिकांश युवाओं को योजनाओं की जानकारी सरकारी माध्यमों के बजाय व्यक्तिगत संपर्कों या सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई।

शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि वर्तमान स्वरूप में ये योजनाएँ ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों जैसे बाँका जिले में शिक्षित बेरोजगारों के लिए अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए अनुसंधान में कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं, जैसे योजनाओं की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पुनःसंरचना, आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण, ब्लॉक स्तर पर हेल्पडेस्क की स्थापना, तथा पंचायत स्तर पर निगरानी समितियों का गठन।

मुख्य शब्द बाँका जिला, शिक्षित बेरोजगार, सरकारी योजनाएँ, मुद्रा योजना, स्वरोजगार, योजना क्रियान्वयन, ग्रामीण बेरोजगारी, युवा सशक्तिकरण।

¹कुमार, संजय (2017). बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं की प्रभावशीलता. पटना विश्वविद्यालय, सामाजिक अध्ययन विभाग।

